HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5983/2016

Universal Sompo General Insurance Company Limited, Through Regional Divisional Manager, Regional Office, Krishna Tower, Upon Kotak Bank, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan, Having Its Corporate Office, LI-94, TTC Industrial Area, MIDC, Mahape, Navi Mumbai, Through Legal Manager

----Appellant/Insurance Company

Versus

1. Smt. Radha Devi W/o Late Murarilal, age 32 years,
2. Kumari Khushboo D/o Late Murarilal, age 17 years,
3. Master Sheetal S/o Late Murarilal, age 15 years,
4. Kumari Shiwani D/o Late Murarilal, age 13 years,
5. Master Vikas S/o Late Murarilal, age 11 years,
   Petitioner No. 2 to 5 minor Through Natural Guardian Mother Smt. Radha Devi W/o Late Murarilal, R/o Pachayawala, Lalpura, Karni Vihar, Jaipur, Rajasthan.
6. Aman Lamba S/o Vinod Kumar Lamba, R/o 94 C, Krishna Nagar, Mathura, Uttar Pradesh

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ritesh Jain, Adv. Ms. Poonam Mishra, Adv. Dr. Ramdeo Arya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Adhiraj Singh Rajawat, Adv. for Mr. Devendra Raghava, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/02/2026

अपीलार्थी–विपक्षी संख्या–2–बीमा कंपनी की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जयपुर शहर, जयपुर द्वारा प्रकरण E.C.C.F.-344/2012 में पारित निर्णय दिनांक **31.08.2016** से

व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से मृतक मुरारी लाल के के परिजनों/दावेदारों/प्रत्यर्थीगण को कुल **6,75,935/—**रूपये प्रतिकर के रूप में व दाह संस्कार के मद में 5,000/—रूपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—बीमा कंपनी तथा प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—बीमा कंपनी का निवेदन है कि मृतक मुरारी लाल के पास घटना के समय कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था, वह प्रत्यर्थी संख्या 6 का कर्मचारी हो और नियोजन काल में उसकी मृत्यु हुई है, यह तथ्य भी सम्यक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी—बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता है। अंत में अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5—दावेदारों की ओर से निवेदन किया गया कि मृतक के ड्राईविंग लाईसेंस तथा मृतक के प्रत्यर्थी संख्या—6 के यहां कर्मचारी के रू॰ में नियोजित होने के संबंध में प्रार्थी पक्ष की और से समुचित साक्ष्य पेश की गयी है तथा उस पर विचार करने के उपरांत ही अपीलाधीन निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि जो आक्षेप लगये गये हैं वे तथ्यों के संबंध में है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में पारित व्यवस्था के अनुसार अधिनियम—1923 की धारा—30 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (Supra) के पैरा संख्या—9, 10, 11 तथा 12 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है—

9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कंपनी की ओर से ड्राईविंग लाईसेंस तथा मृतक व प्रत्यर्थी संख्या 6 के नियोजक व कर्मचारी के संबंधों के बाबत

जो आक्षेप लगाये गये हैं, उसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विरूद्ध अपना निष्कर्ष दिया है। यह निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो अथवा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अन्दाज किया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। उठायी गयी आपत्तियां तथ्यों के संबंध में है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है।

चूंकि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अतः यह अपील खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक **31.08.2016** की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

स्थगन प्रार्थना पत्र भी इसी अनुसार खारिज किया जाता है। अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /62